



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1987/चैत्र 9, 1909

No. 138] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1987/CHAITRA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

उद्घोष मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
नई दिल्ली, 30 मार्च, 1987  
आदेश

का.आ. 268(अ) :—/18कक्ष/आई.डी.आर.ए./87—  
केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक  
विकास मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 134(अ)/18कक्ष/  
आई.डी.आर.ए./79, तारीख 13 मार्च, 1979, द्वारा यथा  
उपांतरित आदेश सं. का.आ. 529(अ)/18कक्ष/आई.  
डी.आर.ए./74 तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे  
इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, बंद<sup>सं</sup>गण उद्योग विभाग परिवर्ती बंगाल सरकार को, (जिसे  
अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, परिवर्ती बंगाल  
मरकार कहा गया है) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त  
प्रधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैमर्स इंडिया बैलिंग एण्ड  
कार्पोरेशन लिमिटेड, सीरमान परिवर्ती बंगाल का (जिसे

इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपकरण कहा गया है)  
तारीख 6 सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि के  
लिये प्रबंध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सोकहित में  
यह समीचीन है कि उक्त प्रधिसूचित आदेश को उपयुक्त  
पांच वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना  
चाहिये और उसमें 31 मार्च, 1987 तक की, जिसके  
अन्तर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिये  
इसे जारी रखने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये  
ये, (देखिए भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग) ---

सं. का.आ. 512(अ)/18कक्ष/आई.डी.आर.ए./79,  
तारीख 4 सितम्बर, 1979,

सं. का.आ. 749(अ)/18कक्ष/आई.डी.आर.ए./80,  
तारीख 5 सितम्बर, 1980,

सं. का.आ. 684(अ)/18कक्ष/आई.डी.आर.ए./81,  
तारीख 4 सितम्बर, 1981,

सं. का.आ. 125(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./82,  
तारीख 5 मार्च, 1982,

सं. का.आ. 648(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./82,  
तारीख 4 सितम्बर, 1982,

सं. का.आ. 158(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83,  
तारीख 4 मार्च, 1983,

सं. का.आ. 386(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83,  
तारीख 31 मई, 1983,

सं. का.आ. 937(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83,  
तारीख 29 दिसम्बर, 1983,

सं. का.आ. 470(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./84,  
तारीख 28 जून, 1984,

सं. का.आ. 947(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./84,  
तारीख 18 दिसम्बर, 1984,

सं. का.आ. 257(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./85,  
तारीख 28 मार्च, 1985, तथा

सं. का.आ. 119(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए. 86  
तारीख 27 मार्च, 1986;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि सोकहित में यह समीक्षित है कि उक्त औद्योगिक उपकरण का प्रबंध उक्त प्राविधिक व्यक्ति द्वारा 31 मार्च, 1988 तक की ओर अवधि के नियंत्रण जाय;

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और वित्तिगमन) प्रविधिम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक को उपलब्ध (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1988 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, कि और अवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[का.सं. 2(14)/80-सी.यू.एस.]  
ए.वी. गोकाक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)  
New Delhi, the 30th March, 1987  
ORDER

S.O. 268(E)/18AA/IDRA/87.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)/18AA/IDRA/74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)/18AA/IDRA/79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary,

Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1987 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development).

Nos. S.O. 512(E)/18AA/IDRA/79, dated the 4th September, 1979,  
S.O. 749(E)/18AA/IDRA/80, dated the 5th September, 1980,  
S.O. 684(E)/18AA/IDRA/81, dated the 4th September, 1981,  
S.O. 125(E)/18AA/IDRA/82, dated the 5th March, 1982,  
S.O. 648(E)/18AA/IDRA/82, dated the 4th September, 1982,  
S.O. 158(E)/18AA/IDRA/83, dated the 4th March, 1983,  
S.O. 386(E)/18AA/IDRA/83, dated the 31st May, 1983,  
S.O. 937(E)/18AA/IDRA/83, dated the 29th December, 1983,  
S.O. 470(E)/18AA/IDRA/84, dated the 28th June, 1984,  
S.O. 947(E)/18AA/IDRA/84, dated the 18th December, 1984,  
S.O. 257(E)/18AA/IDRA/85, dated the 28th March, 1985 and  
S.O. 119(E)/18AA/IDRA/86, dated the 27th March, 1986;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period upto 31st March, 1988;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1988.

[File No. 2(14)/80-CUS]  
A. V. GOKAK, Jt. Secy.